

"जुड़ी अखबार निकलने दो तो मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियमक है और कौन कानून का निर्माता"-वेडेल किलिप्पा

दैनिक भारतीय बस्ती

बस्ती 17 जनवरी 2025 शुक्रवार

सम्पादकीय

निशाने पर मार्क जकरबर्ग

फेसबुक की ओर कंपनी मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग एक बार फिर गलतबयानों के मामले में फंस गए हैं। संसद की आईटी एंड कम्प्युटर्स पार्सन की स्टैंडिंग कमिटी उहरे स्पष्टन करने वाली है। फेसबुक और मेटा पहले भी तथ्यों के साथ छड़ाछड़ा और फेकप्यूजों को लेकर ढिलाई जैसे अरापों में घिरती रही हैं।

मेटा ने अपने सीईओ मार्क जुकरबर्ग द्वारा दिए गए झूठे बयान के लिए मार्की मांगी, जिससे उहरोंने दावा किया था कि भारत उन देशों में शामिल है जहां मौजूदा सरकार को ऑडिट-19 प्रति कानूनिक कारण चुनाव हार गई। मेटा इंडिया के पलिक पॉलिसी उपायकांश जिन्हानें डुकराल ने एक्स पर जुकरबर्ग की ओर से माफी मांगी। मार्क का यह अवलोकन कि 2024 के चुनावों में कई मौजूदा दलों को फिर से नहीं चुना गया, कई देशों के लिए सही है, लेकिन भारत के लिए नहीं। हम इस अनजाने में हुई त्रुटि के लिए क्षमा प्राप्त हैं।

ज्ञात रहे हैं कि अईटी एवं संचार संबंधी संसदीय समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने कहा कि उनकी समिति मेटा इंडिया को तलब करेगी, जिसे अपने सीईओ के झूठे बयान के लिए भारती मांगी। ऑडिट के बाद 20 देशों में सत्ताधारी दल चुनाव हार गए, लेकिन भारत उनमें शामिल नहीं था। निशिकांत दुबे ने एक्स पर एक पोर्ट और कानून, 'भारतीय संसद व सरकार' को 140 करोड़ लोगों का आशीर्वाद व जन विश्वास प्राप्त है। मेटा (मेटा इंडिया) के अधिकारी ने आखिर अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगी है। यह जीत भारत के आम नागरिकों की है। नरेंद्र मोदी को जनता ने तो सरोकारी वार और प्रधानमंत्री को जनता के साथ सरकार के लिए उनकी अद्वितीय वारी की जानकारी के लिए उनका सराहना में रहा।

मेटा इंडिया को जिसके बारे में बताया जाता है कि उनकी समाजी वारी नहीं है। इसके पहले निशिकांत दुबे ने कहा था कि मार्क जुकरबर्ग के इस स्टेटमेंट के लिए मेटा को तलब करिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कीसी भी तात्पुरताकी देवी की गलती जानकारी देश की छिपाई को धूम्रधान करती है। इस गलती की ओर लिए जाने वाले देशों के लिए भारतीय संसद व सरकार को जन विश्वास प्राप्त है। मेटा (मेटा इंडिया) के अधिकारी ने आखिर अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगी है। यह जीत भारत के आम नागरिकों की है। नरेंद्र मोदी को जनता ने तो सरोकारी वार और प्रधानमंत्री को जनता के साथ सरकार के लिए उनकी अद्वितीय वारी की जानकारी के लिए उनका सराहना में रहा।

यह बार्कट हैरत की बात है कि जकरबर्ग ने भारत की भी उन देशों में शामिल कर लिया जाहा है जिसके बारे में भारतीय संसद व सरकार ने सत्तां गवाई। तथ्य यह है कि बीजीपी की भी भैटे भले कम हुई हैं, लेकिन सर्तारपां भगवंधन छहें। वे बहुत हासिल कर सरकारों ने सत्तां गवाई। एक समर्पण नरेंद्र मोदी लगातार तीसीरी वार और अन्य उनकी सरकार बढ़ रही है। इस तथ्य से जकरबर्ग कैसे अनजान हो सकते हैं? क्या वह जानूबज़कर भारत सरकार के बारे में गलत सूचनाएं फैला रहे हैं?

जकरबर्ग ने अभी हाल ही में मेटा की कंटेनर मेनेजमेंट पॉलिसी में बड़े बदलाव की घोषणा की है। अभियक्ति की आजानी की नाम पर लाए जा रहे हैं। इन बदलावों के तहत मेटा थर्ड पार्टी फैटर चीकिंग का सिस्टम समाप्त करने वाली है। उसकी इस घोषणा को भी अमेरिका में हो रहे सत्ता परिवर्तन से जोड़कर देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि यह ट्रॉप समयकों को खुश करने की कोशिश है जो क्री स्पीच के नाम पर पर फैटर चीकिंग की इस व्यवस्था का काफी समय के सिरोंवार कर रहा है। एवं इनका फैटर चीकिंग का लिए खास स्कॉलरिका विवाद को भी इस सर्वोच्च नियमों में देखा जाता है।

यह एसे और भी मामले हैं जिनसे यह संदेह मजबूत होता है कि फेसबुक जैसे सालाल मौड़िया मचों का इस्तेमाल सिर्फ अधिक से अधिक मूफाना हासिल करने के मामसद से हो रहा है। समाज को होने वाले नुकसानों की तरफ पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस तरह की गेर जिम्मेदारी खतरनाक हो सकती है और इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती।

ताजा विवाद को सरकार ने गमीरता से लिया है, यह अच्छी बात है। लेकिन जल्दी है कि चिंता इसी मामले तक सीमित न रहे। हैर एसी और फेक न्यूज़ की अन्य मामले भी जरूर नहीं होंगी हैं। चाहे वे किसी भी सुसाया और मार्टी के खिलाफ कैंडित हों। उमीद है, सरकार की सख्ती मेटा को ज्यादा जिम्मेदार बनाए रखेगी।

महिला सशक्तिकरण में आगे भारतीय रेलवे

-प्रियंका सौरभ-

महिलाओं का सशक्तिकरण शायद

20वीं सदी के बाद से सबसे ज्यादा

रेल ऐसी महिलाओं की प्रेरण कहानीयों

सुनते हैं कि जिन्होंने बुखरू-प्रधान

महिलाओं में अपनी छाप छोड़ी है,

जैसे सार्वजनिक जीवन और सरकार

में उद्योग के कालों के लिए भी क्षेत्र में

महिलाएं अग्रणी हैं और यह वार्षीय

रेलवे के कर्मचारियों में केवल 6-7%

महिलाएं हैं। आज जीवन की बातों

में यहीं है, पुरुष-प्रधान

महिलाओं को उनकी जीवन के लिए उत्तर-पुरुष

महिलाओं को

